ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

3 January 2025

रक्षा उत्पादन में वृद्धि

सन्दर्भ: हाल ही में जारी केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के रक्षा क्षेत्र का अगले पांच वर्षों में लगभग 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की सम्भावना है। यह वृद्धि सरकार के सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी प्रगति से संचालित होगी।

विकास के प्रमुख चालक:

- भारत सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 'मेक इन इंडिया' जैसी नीतियों और उदार एफडीआई मानदंडों ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। इन सुधारों ने न केवल तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेश को भी आकर्षित किया है और घरेलू विनिर्माण को मजबूत किया है।
- रिपोर्ट में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मिलकर रक्षा आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, विशेषकर हथियार, गोला-बारूद, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और नौसेना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में।

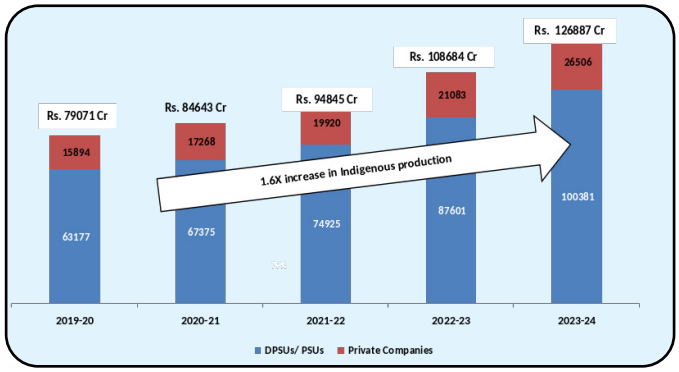

सरकारी बजट और व्यय:

- हाल के वर्षों में देश का रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का 1.90% से 2.8% तक रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस बजट को बढ़ाकर 6.22 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- सरकार ने वार्षिक रक्षा उत्पादन को 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो कि 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर वित्त वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। यह लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर रक्षा महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा:

- भारत स्वदेशी विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक और मिसाइल प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रणनीतिक निवेश और नीतिगत पहल इस बदलाव को मजबूत कर रही हैं।

रक्षा निर्यात में वृद्धि:

- पिछले छह वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 28% की स्वस्थ CAGR से बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 2029 तक लगभग 19% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है।
- इन निर्यातों में विमान, नौसेना प्रणाली, मिसाइल प्रौद्योगिकी और सैन्य हार्डवेयर जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह वृद्धि घरेलू उत्पादन की बढ़ती गुणवत्ता और भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों की वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को दर्शाती है।

चुनौतियाँ और आगे की राह:

- हालाँकि, प्रौद्योगिकी विकास, बुनियादी ढांचे और विनियामक ढांचे जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के सहयोग को मजबूत करना विकास की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, भारत को इन चुनौतियों से पार पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निवेशों को आकर्षित करना चाहिए और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहिए।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर)

सन्दर्भ: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दिसंबर 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, विशेष रूप से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में कमी आई है। यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती और लचीलेपन को दर्शाती है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की मुख्य बिंदु:

- **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात में गिरावट:** सबसे उल्लेखनीय विकास सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में कमी है, जोकि सितंबर 2024 तक घटकर 2.6% हो गई है। यह पिछले 12 वर्षों का सबसे निम्न स्तर है। यह बैंकों द्वारा खराब ऋणों के प्रबंधन में हुए उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती का प्रमाण है।
- **शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनएनपीए) अनुपात:** शुद्ध एनपीए (एनएनपीए) अनुपात 0.6% पर स्थिर रहा, जोकि पर्याप्त प्रावधान करके खराब ऋणों के प्रभावी प्रबंधन का संकेत देता है। इससे

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

पता चलता है कि एससीबी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से संभावित नुकसान को संभालने में मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं।

- **स्लिपेज अनुपात और प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर):** स्लिपेज अनुपात, जोकि मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में नए एनपीए को मापता है, बढ़कर 0.7% हो गया, लेकिन अभी भी प्रबंधनीय बना हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सक्रिय प्रावधान के कारण प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार होकर 77% हो गया।
- **विभिन्न बैंक श्रेणियों में राइट-ऑफ की प्रवृत्ति:** रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी बैंकों के लिए जीएनपीए अनुपात में राइट-ऑफ बढ़ा है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और पीएसबी के लिए इसमें थोड़ी गिरावट आई है। राइट-ऑफ जीएनपीए अनुपात को कम करने में मदद करता है और डेटा से पता चलता है कि बैंक सक्रिय रूप से अपने बहीखातों से खराब ऋणों को कम कर रहे हैं।

अन्य प्रमुख निष्कर्ष:

- भारतीय बैंकों ने मजबूत पूंजी भंडार बनाए रखा है, जिससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।
- आरबीआई के मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है कि अधिकांश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं और प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में भी झटके झेलने में सक्षम हैं।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी) और बीमा क्षेत्र भी स्वस्थ बने हुए हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को और बल मिला है।
- रिपोर्ट में बैंकों की जमा प्रोफाइल में बदलाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसमें सावधि जमा के पक्ष में कम लागत वाली चालू खाता बचत खाता (CASA) जमा में गिरावट आई है।
- ब्याज दर की ओर बदलाव से शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) प्रभावित हो सकता है, जोकि उच्च ब्याज दरों के कारण ग्राहक व्यवहार में बदलाव को दर्शाता है।
- परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (Return on Assets) तथा प्रावधानों एवं करों से पूर्व आय में सुधार के बावजूद, एनआईएम में गिरावट के कारण लाभप्रदता मोटे तौर पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
- भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है। RBI के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (नवंबर 2024) ने भारत की वित्तीय प्रणाली में विश्वास दिखाया, जिसमें भू-राजनीतिक संघर्ष, वैश्विक आर्थिक विकास और पूंजी बहिर्वाह और रुपये के मूल्यह्रास पर चिंताओं के रूप में पहचाने गए प्रमुख जोखिम शामिल हैं।
- जून 2024 तक भारत का घरेलू ऋण अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम यानी सकल घरेलू उत्पाद का 42.9% बना रहेगा।
- पिछले तीन वर्षों में घरेलू ऋण में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण औसत ऋणग्रस्तता में वृद्धि के बजाय उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि है।
- घरेलू ऋण में वृद्धि व्यापक वित्तीय समावेशन अभियान का संकेत देती है, जिसमें ऋण का उपयोग उपभोग, परिसंपत्ति सृजन (गृह और वाहन ऋण) और उत्पादक उद्देश्यों (व्यवसाय और शिक्षा ऋण) के लिए किया जा रहा है।

नौसेना में शामिल होगे वाग्शीर, सूरत और नीलगिरि जहाज

सन्दर्भ: भारतीय नौसेना 15 जनवरी, 2025 को तीन प्रमुख फ्रंटलाइन लड़ाकू जहाजों को कमीशन करेगी: नीलगिरि (प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ फ्रिगेट), सूरत (प्रोजेक्ट 15 बी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर) और वाघशीर (स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बी)। यह विकास रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को उजागर करता है और नौसेना की बढ़ती लड़ाकू क्षमता को दर्शाती है।

- तीनों जहाजों (वाग्शीर, सूरत और नीलगिरी) का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई में किया गया। इसमें जहाज स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं, वही स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप के लाइसेंस के तहत किया गया है।

पनडुब्बी वाग्शीर के बारे में:

- वाग्शीर प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बी श्रृंखला की छठी और अंतिम यूनिट है। फ्रांसीसी नेवल ग्रुप के सहयोग से भारत में निर्मित, यह डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी अपनी कार्यक्षमता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है।
- यह पनडुब्बी एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन युद्ध, निगरानी और विशेष अभियानों सहित विभिन्न मिशनों के लिए सक्षम है। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम लगाए गए हैं और भविष्य में इसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक से लैस किया जा सकता है।

प्रोजेक्ट-15बी स्टील्थ विध्वंसक सूरत के बारे में:

- सूरत, प्रोजेक्ट-15बी स्टील्थ विध्वंसक श्रेणी का चौथा और अंतिम जहाज है। यह कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक का एक उन्नत संस्करण है, जिसमें बेहतर युद्ध क्षमता के लिए डिजाइन, सेंसर और हथियार

प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में अधिकांश स्वदेशी रूप से या वैश्विक सहयोग के माध्यम से विकसित किए गए हैं।

प्रोजेक्ट-17ए फ्रिगेट नीलगिरि के बारे में:

- नीलगिरि, प्रोजेक्ट-17ए फ्रिगेट श्रृंखला का प्रमुख जहाज है। यह शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन है। इसमें बेहतर स्टेल्थ क्षमताएं, कम रडार क्रॉस-सेक्शन और उन्नत तकनीकें हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, नीलगिरि में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर एकीकृत हैं।

नीलगिरि और सूरत में कौन सी क्षमताएं विमानन हैं?

- नीलगिरि और सूरत दोनों जहाज आधुनिक विमानन सुविधाओं से लैस हैं, जोकि उन्हें चेतक, ध्रुव, सी किंग और हाल ही में शामिल किए गए एमएच-60आर जैसे विभिन्न हेलीकॉप्टरों को संचालित करने की क्षमता प्रदान करती हैं।
- इन जहाजों पर लगी सुविधाएं दिन-रात लगातार संचालन के लिए डिजाइन की गई हैं और इनमें रेल-लेस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम और विजुअल एड्स और लैंडिंग सिस्टम जैसी प्रणालियां भी शामिल हैं।

रणनीतिक परिणाम:

- वाग्शीर, सूरत और नीलगिरि का जलावतरण भारत की नौसैनिक युद्ध क्षमता को काफी बढ़ावा देगा। इन प्लेटफार्मों की उन्नत तकनीक और बढ़ी हुई क्षमताएं भारत की समुद्री रक्षा और वैश्विक स्तर पर परियोजना शक्ति को मजबूत करेंगी।

वायनाड भूस्खलन: राष्ट्रीय आपदा घोषित

सन्दर्भ: हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन को 'गंभीर प्रकृति' की राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। यह वर्गीकरण केरल सरकार को पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम बनाएगा। पांच महीने पहले हुई इस प्राकृतिक आपदा में 254 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 128 लोग लापता हो गए थे।

भारत में आपदा की परिभाषा:

- भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, आपदा को 'ऐसी भयावह घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो जीवन की भारी क्षति, मानवीय पीड़ा, संपत्ति की क्षति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इससे प्रभावित समुदाय की इससे निपटने की क्षमता खत्म हो जानी चाहिए।'

आपदा के प्रकार:

- आपदाएँ प्राकृतिक या मानवजनित हो सकती हैं।
  - » **प्राकृतिक आपदाएँ:** भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि।
  - » **मानवजनित आपदाएँ:** परमाणु, जैविक या रासायनिक घटनाएँ, दुर्घटनाएँ या लापरवाही के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाएँ।

राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के नियम:

- किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई निश्चित कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि, आम तौर पर किसी राज्य की एक तिहाई आबादी को प्रभावित करने वाली और 'दुर्लभ गंभीरता' वाली आपदा को राष्ट्रीय आपदा माना जा सकता है। यह निर्णय आपदा की तीव्रता, प्रभावित क्षेत्र के आकार और राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन क्षमता जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

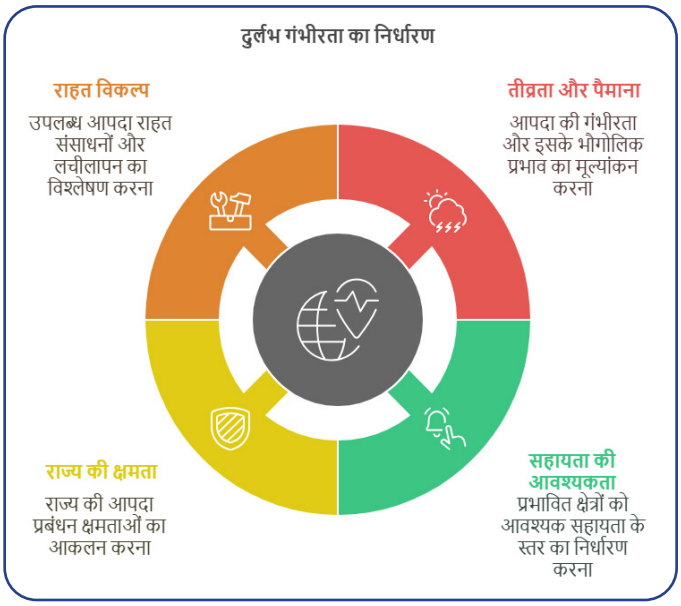

दुर्लभ गंभीरता निर्धारित करने के कारक:

- किसी आपदा को 'दुर्लभ गंभीरता' की श्रेणी में रखने के लिए निम्नलिखित कारकों का मूल्यांकन किया जाता है:
  - » **आपदा की तीव्रता और पैमाना:** आपदा कितनी गंभीर थी और इसका प्रभाव कितने बड़े क्षेत्र पर पड़ा था?
  - » **आवश्यक सहायता का स्तर:** प्रभावित क्षेत्रों को कितनी सहायता की आवश्यकता है?
  - » **आपदा से निपटने की राज्य की क्षमता:** प्रभावित राज्य अपनी क्षमताओं से आपदा से कितना निपट सकता है?
  - » **राहत योजनाओं में उपलब्ध विकल्प और लचीलापन:** राज्य सरकार के पास आपदा राहत के लिए कितने विकल्प और

संसाधन उपलब्ध हैं?

गंभीर आपदाओं के उदाहरण:

- गंभीर मानी जाने वाली आपदाओं के उदाहरणों में 2013 की उत्तराखंड बाढ़ और 2014 में आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात हुदहुद शामिल हैं , जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान की गई थी।

राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लाभ:

- जब किसी आपदा को 'दुर्लभ गंभीरता' की घोषित किया जाता है, तो प्रभावित राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्राप्त होती है, जिसमें शामिल हैं:
  - » राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त धनराशि।
  - » आपदा राहत कोष (सीआरएफ) जिसमें केन्द्र और राज्य के बीच 3:1 का अंशदान होता है।
  - » यदि सीआरएफ अपर्याप्त हो तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से अतिरिक्त सहायता।
  - » ऋण चुकौती सहायता या रियायती ऋण।

आपदा राहत के लिए वित्तपोषण:

आपदा राहत के लिए वित्तपोषण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 का अनुसरण करती है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) बड़े संकटों से निपटने के लिए एनसीएमसी जिम्मेदार होती है।
- केंद्रीय टीमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती हैं और क्षति का आकलन करती हैं।
- केंद्रीय गृह सचिव एक अंतर-मंत्रालयी समूह का नेतृत्व करते हुए मूल्यांकन की समीक्षा करते हैं।
- उच्च स्तरीय समिति वित्तीय सहायता को मंजूरी देती है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

उत्तराखंड में महाभारत पर आधारित उद्यान

- उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत से प्रेरित एक अनूठा एथनोबोटैनिकल गार्डन विकसित किया है। इस गार्डन का उद्देश्य महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ज्ञान को उजागर करना है।
- गार्डन में खैर (अकेसिया कैटेचू), कोविदर (बौहिनिया वेरिएगाटा), बरगद (फिकस बेंघालेंसिस), पीपल (फिकस रिलिजियोसा) और ढाक (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा) सहित 37 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ लगाई गई हैं।
- महाभारत के वन पर्व/अरण्य पर्व में वृक्षारोपण, जलाशय निर्माण और बाघों की रक्षा जैसे पर्यावरण संरक्षण के विचारों का उल्लेख है। यह उद्यान उन विचारों को पुनर्जीवित करने और समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास है।
- इसके साथ ही, हल्द्वानी में "रामायण वाटिका" भी स्थापित की गई, जो इसी प्रकार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय पहल का हिस्सा है। यह उद्यान पर्यावरणीय शिक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है और स्थानीय समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है।

वितुल कुमार: सीआरपीएफ के महानिदेशक

Vitul Kumar has been assigned an additional charge of Director General (DG), Central Reserve Police Force (CRPF). He is a 1993 batch IPS officer of UP cadre.

- आईपीएस अधिकारी वितुल कुमार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक का पदभार संभाला। इससे पहले, वे सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। गृह मंत्रालय ने उन्हें मौजूदा प्रमुख अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया।
- वितुल कुमार को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएम) और पुलिस पदक (पीएम) सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2016 में उन्हें महानिदेशक की रजत प्रशस्ति डिस्क से भी नवाजा गया था।
- उनका कार्यकाल बल की प्रभावशीलता बढ़ाने और नई चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण होगा। जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती, वे कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उनके नेतृत्व में सीआरपीएफ अपने अभियान और प्रशिक्षण में नए आयाम स्थापित कर सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने 2025 सुधारों का वर्ष घोषित किया

- रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को "सुधारों का वर्ष" घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य सशस्त्र बलों को आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और बहु-डोमेन संचालन के लिए तैयार बनाना है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, और खरीद प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर युद्ध जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करने की योजना है।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर भारत को रक्षा उपकरणों का विश्वसनीय निर्यातक बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, वेटेरन कल्याण कार्यक्रमों में सुधार भी प्राथमिकता पर है। यह पहल भारत की सैन्य क्षमताओं को विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाने का एक बड़ा कदम है।

ओएनओएस: एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना

- सरकार ने 1 जनवरी, 2025 से 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (ओएनओएस) योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को शोध पत्रों और डिजिटल संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है।
- योजना के तहत 13,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों में उपलब्ध होंगी। इसके लिए तीन वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- इस पहल के तहत 1.8 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा, जिससे ज्ञान की समान उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, अच्छी गुणवत्ता वाली ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए लाभार्थी लेखकों को सालाना 150 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
- ओएनओएस भारत को डिजिटल शिक्षा में एक अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2020 में 7.93% की कमी दर्ज की गई। 2005 से 2020 के बीच भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है।
- 2020 में, भारत का कुल उत्सर्जन 2,959 मिलियन टन CO_2 के बराबर था। भूमि उपयोग परिवर्तन को छोड़कर, यह उत्सर्जन 1994 से 98.34% बढ़ा है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और 50% विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना है।
- भारत की यह प्रगति जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

2024 के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

- हाल ही में, भारत सरकार ने खेलों में असाधारण योगदान के लिए 2024 के प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है।

पुरस्कार विजेता:

- **मनु भाकर (निशानेबाजी):** मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इतिहास रच दिया, जब वह स्वतंत्रता के बाद खेलों के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गईं।
- **हरमनप्रीत सिंह (हॉकी):** भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में, हरमनप्रीत सिंह ने टीम को पेरिस में लगातार दूसरे ओलंपिक कांस्य पदक दिलाया।
- **प्रवीण कुमार (पैरा एथलेटिक्स):** प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी64 श्रेणी में पेरिस पैरालिंपिक में स्वर्ण पदक जीता।
- **डी गुकेश (शतरंज):** डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में:

- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 1991-1992 में स्थापित, यह असाधारण अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए एथलीटों को मान्यता देता है। शुरू में राजीव गांधी के नाम पर रखे गए इस पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में महान फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया।